पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 जून, 2021 ई0 (ज्येष्ठ 22, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	373–384	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	231–235	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

09 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 183/XX-4/2021–1(21)/2019–राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 की उपधारा (1) सपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–428/बीस–4/2017–1(17)/2009 टी0सी0, दिनांक 21–06–2017 व अन्य पूर्व नीतियों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य की कारागार में निरूद्ध हो, को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के सुअवसर पर शेष सजा का परिहार प्रदान कर सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थायी नीति बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(1) इसका नाम उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

(3) इसका विस्तार उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहें वह उत्तराखण्ड राज्य अथवा उत्तराखण्ड से बाहर अन्य राज्य की कारागारों में निरूद्ध हो, पर होगा।

(4) यह नीति उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हो, किन्तु यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(क) ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बन्दियों पर,

(ख) ऐसे सिद्धदोष बन्दियों पर, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित हो,

(ग) ऐसे बन्दियों पर, जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष है, जिनके लिए सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति किसी विधि में अनुमन्य नहीं है,

(घ) ऐसे बन्दियों पर, जिनकों मा0 न्यायालय द्वारा जीवनपर्यन्त कारागार में निरूद्ध रखे जाने के आदेश दिये गये हैं।

परिभाषाएं 2 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नीति में :–

(क) 'मुख्यमंत्री' से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री अभिप्रेत है,

(ख) 'समिति' से उत्तराखण्ड शासन के गृह विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है।

(ग) 'महानिरीक्षक कारागार' से कारागार विभाग के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक कारागार अभिप्रेत है।

(घ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ङ.) 'वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक' से सम्बन्धित कारागार के प्रभारी वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक अभिप्रेत है।

सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु समिति का गठन

3 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत आजीवन कारावासित सिद्धदोष बन्दियों को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के सुअवसर पर समयपूर्व मुक्ति/सजामाफी अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकाओं के निस्तारण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2–प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी अथवा उनके द्वारा नमित कोई अपर सचिव, न्याय/अपर विधि परामर्शी	सदस्य
3–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित कोई अन्य सचिव	सदस्य
4–अपर सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5–महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव

सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति हेतु विचारणीय पात्रता

4 (क) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त महिला सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं हैं तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की अपरिहार तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

(ख) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सभी पुरूष सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

(ग) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके संबंध में उत्तराखण्ड जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या–195 में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:–

1. Advanced bilateral pulmonary tuberculosis
2. Incurable malignancy
3. Incurable Blood diseases
4. Congestive heart failure
5. Chronic epilepsy with mental degeneration
6. Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer
7. Total blindness of both eyes
8. Incurable paraplegias and hemiplegics
9. Advanced Parkinsonism
10. Brain Tumor
11. Incurable Aneurysms
12. Irreversible Kidney failure

(घ) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 12 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

(ड.) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

(च) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के प्रस्तर xiii में वर्णित अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नही है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

प्रतिबन्धित श्रेणी

5 (i) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।

(ii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो।

(iii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से जीवन–पर्यन्त कारागार में निरूद्धि हेतु आदेशित किया है अथवा आजीवन कारावास से दण्डित समस्त ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट समय निर्धारित कर निरूद्धि हेतु आदेशित किया गया है।

(iv) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके वाद का अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिये सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था।

(v) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिन पर संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे साथ–साथ भोगे जाने वाली पृथक–पृथक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब किये गये अपराधों के सम्बन्ध में ऐसे दण्डादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है।

(vi) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हें सामूहिक नरसंहार (तीन या तीन से अधिक हत्याएं) की घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषसिद्ध किया गया हो।

(vii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो निरूद्धि की अवधि में विगत 02 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–814 के अन्तर्गत चेतावनी से भिन्न किसी भी लघु दण्ड से और विगत 05 वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–815 के अन्तर्गत किसी भी वृहद दण्ड से कारागार प्रशासन द्वारा दण्डित किए गये हों।

(viii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हें दण्डादेश निलम्बन/पैरोल/गृह अवकाश के दौरान किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(ix) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्होने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो।

(x) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(xi) ऐसे सिद्धदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नही हैं।

(xii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे निम्न अधिनियमों के तहत दोषसिद्ध किया गया हो :–
–नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985
–आतंकवादी और विध्वंशकारी कियाकलाप अधिनियम 1997
–आतंकवादी गतिविधि प्रतिषेध अधिनियम, 2002
–स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं0 61)
–स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का सं0 42)
–सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का सं0 52)
–शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923
–विदेशियों विषयक अधिनियम 1946
–विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974
–लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012(POCSO ACT 2012)

(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण), 364 ए (मुक्ति–धन आदि के लिए व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्पेरित करना), 366 ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366बी (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों।

(xiv) पेशेवर हत्यारे जो भाड़े पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों।

(xv) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के अन्तर्गत राज्य के खिलाफ युद्ध करने या युद्ध का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के दोषी पाये गये हों।

(xvi) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो सरकारी सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान उसकी हत्या के दोषी हों।

प्रकिया 6 (क) समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बंदियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगें एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नही है तथा पात्र समस्त बन्दियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी समयपूर्व रिहाई

का प्रस्ताव महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें।

(ख) बंदियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।

(ग) महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवंबर तक प्रेषित कर दिया जायेगा।

(घ) शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त समिति बन्दियों के सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचार–विमर्श करेगी।

(ड.) बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचारोपरान्त् समिति अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को अग्रसासित करेगी।

(च) सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जायेगा।

सजामाफी पर बन्दियों को कारागार से रिहा किया जाना 7. राज्यपाल के अनुमोदन/आदेशोपरान्त् आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदियों को इस शर्त पर कारागार से मुक्त किया जायेगा कि वह विधि सम्मत आचरण बनाये रखने के लिये रूपया 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपनी मुक्ति से पूर्व संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

गलत रिहा किये गये बन्दियों को पुनः निरूद्ध किया जाना 8. उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बंदी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा दी गयी सजा उसे पूर्ण रूप से भुगतना चाहिये, तो शासन ऐसे बंदी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये उसे पुनः कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification **No. 183/xx-4/2021-1(21)/2019,** dated February 09, 2021 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

February 09, 2021

No.183/xx-4/2021-1(21)/2019 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 432 read with section 433 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and in supersession of Government order No. 428/twenty-4/2017-1(17)/2009 TC. dated 21-06-2017 and other previous policies, the Governor is pleased to make the following permanent policy regarding sentence pardon/ premature release by remission of remaining sentence on occasion of Republic Day (26 January) of, convicted prisoner punished with sentence of life imprisonment by Court located in Uttarakhand State even they are detained in Jail of other State outside the State of Uttarakhand-

The Uttarakhand State (for Sentence Pardon/ Premature Release of Convicted Prisoners Punished with Life Imprisonment by Court) Permanent Policy, 2021

Short title and commencement

1. (1) The Uttarakhand State (for Sentence Pardon/ Premature Release of Convicted Prisoners Punished with Life Imprisonment by Court) Permanent Policy, 2021.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall extend to convicted prisoners punished by a court located in the State of Uttarakhand whether he/she is detained in a Jail of Uttarakhand State or in a State outside Uttarakhand.

(4) This Policy shall apply to the prisoners convicted by the courts in Uttarakhand for offence to which the executive power of the State extends whether detained in Jail within the State of Uttarakhand or outside the State but shall not apply to following-

(a) on the prisoners convicted for an offence to which the executive power of the State does not extend;

(b) on the prisoners against whom any other criminal case is pending before any Court;

(c) on such prisoners convicted for an offence for which sentence pardon / premature release is not admissible under any law;

(d) on such prisoners, who have been ordered by a Court of Law to the detained till life time.

Definitions

2. In this policy, unless there is anything repugnant in the subject or context –

(a) "Chief Minister" means Chief Minister of Uttarakhand State;

(b) "Committee" means Committee constituted under the Chairmanship Principal Secretary/ Secretary of Home Department, Government of Uttarakhand ;

(c) "Inspector General Jail" means Head of Department of Jail Department Inspector General Jail;

(d) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(e) "Senior Superintendent Jail / Superintendent Jail " means Incharge Senior Jail Superintendent/ Superintendent of concerned Jail;

Constitution of Committee for consideration regarding sentence pardon/ premature release of convicted prisoners

3. The following committee is being constituted for the disposal of mercy petition presented by the convicted prisoners or their relatives for premature release, Sentence, pardon or for any other deduction on the occasion of Republic Day (26 January) under Article 161 of the constitution of India:-

(1) Principal Secretary/ Secretary, Home (Jail) Government of Uttarakhand- Chairman;

(2) Principal Secretary/ Secretary, Law and Legal Remembrance or any Additional Secretary Law/ Additional Law Remembrance nominated by him- Member;

(3) Any other Secretary nominated by Principal Secretary/ Secretary Home Department- Member;

(4) Additional Secretary, Home (Jail) Government of Uttarakhand- Member;

(5) Inspector General Jail, Uttarakhand, Dehradun- Member-Secretary.

Consideration of eligibility for sentence pardon/ premature release

4. (a) All female convicted prisoners punished with life imprisonment whose offence is not covered by sub para marked in prohibition category as mentioned in para 5 and who has served the sentence of fourteen years without remission and sixteen years with remission including the period during trial.

(b) All female convicted prisons punished with life imprisonment whose offence is not covered by sub para marked in prohibition category as mentioned in para 5 and who has served the sentence of sixteen years without remission and twenty years with remission including the period during trial.

(c) All convicted prisons punished with life imprisonment whose offence is not covered by sub para marked in prohibition category mentioned is para 5 and who are suffering from any of the following diseases and in respect of which a certificate to the effect is given by medical board as provisioned in para No- 195 of Uttarakhand Jail manual and who has served the sentence of ten years without remission and twelve years with remission including the period during trial-

1. Advanced bilateral pulmonary tuberculosis.
2. Incurable malignancy.
3. Incurable Blood diseases.
4. Congestive heart failure.
5. Chronic epilepsy with mental degeneration.
6. Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer.
7. Total blindness of both eyes.
8. Incurable paraplegias and hemiplegics
9. Advanced Parkinsonism

10. Brain Tumor.

11. Incurable Anneurysms

12. Irreversible Kidney failure.

(d) All convicted prisoners punished with life imprisonment whose offences are not covered by sub para marked in prohibition category as mentioned in para 5 and who have completed the age of seventy years and had served sentence of twelve years without remission and fourteen years with remission including the period during trial.

(e) All convicted prisoners punished with life imprisonment whose offence are not covered by sub para marked in prohibition category as mentioned para 5 and who has completed the age of Eighty years and has served sentence of the ten years without remission and twelve years with remission including the period during trial.

(f) All convicted prisoners punished with life imprisonment whose offence are not covered by any other sub para except offence mentioned in sub para xiii of prohibition category in para 5 further who has served the sentence of twenty years without remission and twenty five years with remission .

Prohibited category 5 (i) All such convicted prisoner punished with life imprisonment by whom application regarding release has not been given.

(ii) All such convicted prisoner punished by life imprisonment who are punished conviction by court situated outside the Uttarkhand State.

(iii) All such convicted prisoner in whose decision order for life time detention in Jail is given by court or all such prisoner convicted with life imprisonment in whose decision it is ordered for detainment by determined special time by Hon'ble Court.

(iv) All such convicted prisoners punished by life imprisonment whose plaint investigation is done by Delhi special police establish such constituted under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No 25 of 1946) or by any other agency competent for investigating offence under Act, other than the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974)

(v) Such convicted prisoner who are convicted for such offence some of which are related to such subject on which executive power of Union Government extends and to whom separate sentence of imprisonment is served

collectively. Any order to suspend remit or commute the sentence given by the State Government shall be applicable regarding him when order to suspend, remit or commute the sentence regarding the offence committed is given by central Government.

(vi) All such convicted prisoner punished with life imprisonment who have convicted offence related to culpable homicide(three or more than three murder).

(vii) All such convicted prisoner punished with life imprisonment who are punished by Jail Administration with any major punishment under para 815 of the Uttar Pradesh Jail Manual (as applicable to the State of Uttarakhand), during last five years and with minor punishment other than warning under para 814 of Uttar Pradesh Jail Manual (as applicable in the State of Uttarakhand), during last two years during detention term.

(viii) Such convicted prisoner punished with life imprisonment who are convicted for any offence during suspension/ parole / furlough.

(ix) All such convicted prisoners punished with life imprisonment who have migrated from Jail during detention term.

(x) Such convicted prisoners who are punished with life imprisonment in more than one criminal matters.

(xi) Such convicted prisoners who are not Indian citizen.

(xii) All such convicted prisoners punished with life imprisonment who are convicted under following Act-

- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
- The Terrorism and Disruptive Activities Act, 1997
- The Prevention of Terrorism Act, 2002
- The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (Act No. 42 of 1988).
- The Customs Act, 1962 (Act no. 52 of 1962).
- The Official Secrets Act, 1923.
- The Foreigners Act, 1946.
- The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.
- The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(xiii) All such convicted prisoners who are punished with

sentence of life imprisonment for offences under section 363A (Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging), 364 (Kidnapping or abducting in order of murder), 364 A (Kidnapping for ransom, etc.) , 366 (Kidnapping , abducting or inducing women to compel her marriage, etc.), 366-A (Procuration of minor girl). 366.B (importation of girl from foreign country), 367 (Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc.), 368 (wrongfully, concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person), 369 (Kidnapping or abducting child ten years with intent to steal from its person), 372(Selling minor for purposes of prostitution, etc.) 373 (Buying minor for purposes of prostitution, etc.) and 376 (Punishment for rape) of the Indian Penal Code, 1860.

(xiv) Professional killers who are guilty contract killing.

(xv) All such convicted prisoner who are found guilty of waging war or attempt to wage war or abetting against the Government under section 121 to 130 of the Indian Penal Code.

(xvi) All such convicted prisoner punished with life imprisonment who are guilty of murder of Government servant during his duty fulfillment.

Procedure

6. (a) All senior superintendent/ superintendent / Incharge Superintendent shall Jail examine the eligibility according to policy/ guidelines determined under above mention para of all such convicted prisoner punished with life imprisonment detained in Jail and shall make sure that no eligible person is left and shall provide proposal related to all eligible prisoners of their pre mature release in annexed proforma to Inspector General Jail Uttarakhand till date 31 October every year.

(b) Age and sentence of prisoner shall be calculated according to 26 January of coming year.

(c) Inspector General Jail while examining the received proposal regarding release of prisoner in light of said policy shall present the proposal to Government till 30 October of every year.

(d) After receiving proposal regarding prisoners release at Government level committee shall consider the matter of sentence Pardon/ premature release of prisoner.

(e) After considering the matter of sentence pardon/ premature release committee shall forward its recommendation to Governor through Government.

(e) Final decision regarding sentence pardon/ premature release of convicted prisoner shall be taken by Governor.

Releasing of prisoner on sentence pardon form Jail

7. After order/ approval of Governor convicted prisoners punished with life imprisonment shall be released from Jail on condition that he shall produce a one personal bond of amount not more than 50,000.00 (Rs. Fifty thousand only) before Senior Superintendent/ Superintendent of jail his release for maintaining law full conduct.

Again detention of prisoner released wrongfully

8. If by mistake such prisoner is released under said orders whose offence in view of State Government is in such category for which he should serve the sentence given by court completely than Government may while canceling the exemption given in sentence of such prisoner detain him again in Jail to serve the remaining sentence.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/234—भाग 1—2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 जून, 2021 ई0 (ज्येष्ठ 22, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICE AUTHORITY, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over Charge)

April 15, 2021

No. 25/2021/PLA, Nainital---Certified that in compliance of Hon'ble High Court Notification No.69/UHC/Admin.A/2021, dated: April, 08, 2021, the charge of the Court and Office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital was handed over by me as here in denoted in the evening of 15.04.2021.

BRIJENDRA SINGH,

Counter Signed,

R.K. KHULBE,

Member Secretary,

Uttarakhand State Legal Service Authority, Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over Charge)

April 15, 2021

No. 62/2021/Family Court, Nainital--Certified that in compliance of Hon'ble High Court Notification No.69/UHC/Admin.A/2021, dated: April, 08, 2021, the charge of the Court and Office of Judge, Family Court, Nainital was handed over by me as here in denoted in the evening of 15.04.2021.

BRIJENDRA SINGH,

Counter Signed,

Illegible,

I/c Registrar General,

Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.

NOTIFICATION

May 21, 2021

No. 190/XIV/a-37/Admin.A/2020--Shri Anurag Tripathi, Civil Judge, (Junior Division), Rudraprayag, District Rudraprayag is hereby sanctioned medical leave for 22 days *w.e.f.* 04.04.2021 to 25.04.2021.

NOTIFICATION

May 21, 2021

No. 191/XIV/a-38/Admin.A/2020--Ms. Shubhangi Gupta, 2nd Addl. Civil Judge (Junior Division), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned Medical leave for 21 days *w.e.f.* 05.04.2021 to 25.04.2021.

NOTIFICATION

May 21, 2021

No. 192/XIV/a-39/Admin.A/2020--Shri Ashish Tiwari, Civil Judge (Junior Division), Uttarkashi, District Uttarakashi is hereby sanctioned Medical leave for 21 days *w.e.f.* 05.04.2021 to 25.04.2021.

NOTIFICATION

May 21, 2021

No. 193/XIV/a-34/Admin.A/2016--Shri Amit Bhatt, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 24.04.2021 to 07.05.2021 with permission to suffix 08.05.2021 & 09.05.2021 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

May 22, 2021

No. 194/XIV-87/Admin.A/2003--Ms. Shadab Bano, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 20 days *w.e.f.* 20.04.2021 to 09.05.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

May 22, 2021

No. 196/UHC/Stationery/2021--The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to suspend the civil work, in the month of June, 2021, only for one week, i.e. from 01.06.2021 to 07.06.2021 in districts Dehradun (except Chakrata outlying court), Hardwar and Udham Singh Nagar alongwith Haldwani and Ramnagar (Outlying Courts District Nainital), Kotdwar (Outlying Court District Pauri Garhwal) and Tanakpur (Outlying Court District Champawat). For rest of the period, the civil work will go on as usual.

The recess will be admissible to all the Judicial Officers, irrespective of the cadre, posted in the stations for 07 days from 01.06.2021 to 07.06.2021 in districts Dehradun (except Chakrata outlying court), Hardwar and Udham Singh Nagar alongwith Haldwani and Ramnagar (Outlying Courts District Nainital), Kotdwar (Outlying Court District Pauri Garhwal) and Tanakpur (Outlying Court District Champawat). During this period, one Officer either from Civil Judge (J.D.) cadre or Civil Judge (S.D.) cadre (whoever is available in the District) will remain present at the station and will dispose off the urgent work of Civil and Criminal nature as per rule. Recess will be admissible to such Officer from 08.06.2021 to 14.06.2021.

By Order of the Hon'ble Court,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

May 24, 2021

No. 197/XIV/13/Admin.A/2008--Shri Manish Kumar Pandey, Additional Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, Nainital is hereby sanctioned Earned leave for 18 days w.e.f. 22.04.2021 to 09.05.2021 with permission to prefix 21.04.2021 as Ram Navami Holiday & suffix 10.05.2021 & 11.05.2021 as weekly holiday.

By Order of Hon'ble the Judge Incharge Education, UJALA,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 24, 2021

No. 198/UHC/Admin.A/2021--In exercise of the powers conferred by Article 225 and Article 227 of the Constitution of India read with Rule 1 (ii) and Rule 2 (vii) of the 'High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020', the High Court of Uttarakhand, Nainital is pleased to notify as following, namely:

1. The ' High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules-2020' shall apply to all suits, appeals, proceedings and matters in the High Court of Uttarakhand, Nainital and all the Civil and Criminal Courts, Tribunals, Family Courts, Special Courts, Juvenile Justice Boards, etc. subordinate to the High Court of Uttarakhand, Nainital and shall come into force from 1st day of June, 2021.

2. So far as may be the 'Google Meet', shall be the "Designated Video Conferencing Software" for time being to be used for the purpose of video conferencing under the Rules, or, if it is not available, 'Jitsi Meet' shall be used as the Designated Video Conferencing Software" for the purpose of video conferencing under the Rules.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

May 24, 2021

No. 199/XIV-a/29/Admin.A/2012--Ms. Vibha Yadav, the then Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh, presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 27 days *w.e.f.* 22.04.2021 to 18.05.2021 with permission to prefix 21.04.2021 as Ram Navami holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

May 24, 2021

No. 200/XIV-30/Admin.A/2008--Shri Man Mohan Singh, Civil Judge (Senior Division), Rishikesh, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 12.04.2021 to 21.04.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/234–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।